भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5517
दिनांक 26 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केन्द्रों का डिजिटलीकरण

5517. श्रीमती कनिमोझीः
श्री डी॰ रविकुमारः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत सरकार ने देश भर के आंगनवाड़ी केन्द्रों की प्रभावी निगरानी संबंधी डाटा के डिजिटलीकरण को प्रारंभ किया है;
(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे डिजिटलीकरण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है;
(ग) इसे पूरा करने के लिए अनुप्रयुक्त तंत्र और रणनीति का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों के उक्त डिजिटलीकरण को पूरा करने हेतु कोई समय-सीमा प्रस्तावित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के पोषण, साक्षरता और अंकीय कौशल में सुधार करने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या पहलें की गई हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : आईसीडीएस स्कीम में मासिक, तिमाही एवं छमाही आधार पर नियमित रिपोर्टों के माध्यम से एक मानकीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से विभिन्न इनपुट प्रक्रिया, आउटपुट एवं प्रभाव संकेतकों के संबंध में स्कीम की भौतिक प्रगति का जायजा लेने के लिए इसकी शुरूआत से एक अंतर्निर्मित तंत्र है । आंगनवाड़ी सेवा स्कीम की निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का डाटा ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए आईसीडीएस - रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम (आरआरएस) नामक संशोधित एमआईएस भी शुरू किया गया है । आईसीडीएस-आरआरएस के तहत प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र को 11 डिजिट का एक विशिष्ट कोड आबंटित किया जाता है तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पर्यवेक्षक के स्तर पर लॉगइन पासवर्ड आबंटित किया जाता है । 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1372872 क्रियाशील आंगनवाड़ी केंद्रों में से 1361714 आंगनवाड़ी केंद्रों को 11 डिजिट का विशिष्ट कोड आबंटित किया गया है । राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है । शेष आंगनवाड़ी केंद्रों को 11 डिजिट का विशिष्ट कोड आबंटित करने का कार्य चल रहा है ।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण अभियान मिशन के तहत आईसीडीएस-सीएएस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की शुरूआत के साथ भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल करने का कार्य शुरू किया गया है । आईसीडीएस-सीएएस मोबाइल आधारित सॉफ्टवेयर विकास चार्टों की ऑटो प्लॉटिंग के आधार पर अल्पवज़नी बच्चों की पहचान को संभव बनाता है । राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध ड्रिलडाउन डैशबोर्ड कुपोषण की समस्या की पहचान एवं निदान में योगदान करता है । इस प्रकार, समग्र सेवा-प्रदायगी में सुधार होता है । 30 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 355000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां आईसीडीएस-सीएएस एप्लीकेशन का प्रयोग कर रही हैं । राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-।। में उपलब्ध है ।

(ग) और (घ) : पोषण अभियान के तहत ऑनलाइन डाटा प्रदान करने के लिए पर्यवेक्षकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन दिए जाते हैं । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजना को लागू करने के तंत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित समीक्षा, बैठकें तथा अधिकारियों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दौरे शामिल हैं । पोषण अभियान के तहत गतिविधियों को कार्यान्वित करने की समय-सीमा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मार्च, 2020 है ।

(ड.) : आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत लाभार्थी बच्चों को दिशानिर्देशों के अनुसार पूरक पोषण दिया जाता है । बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मासिक ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस तथा समुदाय आधारित समारोहों का आयोजन किया जाता है । स्कूल-पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत प्रदान की जाने वाली दूसरी सेवा है । इसके तहत, 3-6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा शामिल है । 5,000/-रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए स्कूल-पूर्व शिक्षा किट के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान की जाती हैं । आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने-अपने आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों की साक्षरता तथा संख्यात्मक कौशलों में सुधार कर सकें ।

*****

अनुलग्नक-I

'आंगनवाड़ी केन्द्रों का डिजिटलीकरण' विषय पर श्रीमती कनिमोझी और श्री डी॰ रविकुमार द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5517 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों का स्टेटस जिन्हें 11 डिजिट का विशिष्ट कोड आबंटित किया गया है

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र	क्रियाशील आंगनवाड़ी केंद्र	आंगनवाड़ी केंद्र जिन्हें आरआरएस के माध्यम से विशिष्ट कोड आबंटित किया गया है
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	720	720	717
2	आंध्र प्रदेश	55607	55607	55531
3	अरुणाचल प्रदेश	6225	6225	6160
4	असम	62153	62153	61700
5	बिहार	115009	99583	99583
6	चंडीगढ़	450	450	450
7	छत्तीसगढ	52474	51215	51215
8	दादर और नागर हवेली	302	302	303
9	दमन और दीव	107	107	102
10	दिल्ली	10897	10897	10908
11	गोवा	1262	1262	1263
12	गुजरात	53029	53029	53092
13	हरियाणा	25962	25962	25987
14	हिमाचल प्रदेश	18925	18925	18947
15	जम्मू और कश्मीर	31938	29599	28737
16	झारखंड	38432	38432	38438
17	कर्नाटक	65911	65911	66002
18	केरल	33318	33244	33144
19	लक्षद्वीप	107	107	107
20	मध्य प्रदेश	97135	97135	97851
21	महाराष्ट्र	110486	110219	104252
22	मणिपुर	11510	11510	11542
23	मेघालय	5896	5896	5896
24	मिजोरम	2244	2244	2244
25	नागालैंड	3980	3980	0
26	ओडिशा	74154	72587	72560
27	पुद्दुचेरी	855	855	855
28	पंजाब	27314	27279	27279
29	राजस्थान	62010	61974	61316
30	सिक्किम	1308	1308	1308
31	तमिलनाडु	54439	54439	54535
32	तेलंगाना	35700	35634	35634
33	त्रिपुरा	10145	9911	9885
34	उत्तर प्रदेश	190145	187997	187997
35	उत्तराखंड	20067	20067	20067
36	पश्चिम बंगाल	119481	116107	116107
	कुल	1399697 [भारत सरकार द्वारा पहले संस्वीकृत किए गए 1400000]	1372872	1361714

अनुलग्नक-II

'आंगनवाड़ी केन्द्रों का डिजिटलीकरण' विषय पर श्रीमती कनिमोझी और श्री डी॰ रविकुमार द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5517 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आईसीडीएस-सीएएस का प्रयोग करने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या (30.06.2019 तक)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	640
2.	आंध्र प्रदेश	55560
3.	बिहार	26618
4.	चंडीगढ़	450
5.	छत्तीसगढ़	10473
6.	दादर और नागर हवेली	303
7.	दमन और दीव	102
8.	हिमाचल प्रदेश	7596
9.	झारखंड	10715
10.	मध्य प्रदेश	27800
11.	महाराष्ट्र	107444
12.	मेघालय	43
13.	मिजोरम	2244
14.	नागालैंड	3334
15.	पुदुचेरी	837
16.	राजस्थान	18739
17.	सिक्किम	818
18.	तमिलनाडु	18573
19.	तेलंगाना	11037
20.	उत्तर प्रदेश	50620
21.	उत्तराखंड	1696
	कुल	355642